

दिल्ली
अधिकतम तापमान 31 डिग्री
न्यूनतम तापमान 20 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 30 डिग्री
न्यूनतम तापमान 19 डिग्री

गुरुवार 16 अक्टूबर 2025
सूर्योदय प्रातः 06:23 बजे
सूर्यास्त सांय 17:50 बजे

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज



पृष्ठ 4 इस्त्राइल-हमास युद्धविराम: किरण या अस्थायी विराम?

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित **वर्ष: 16 अंक: 362** गाजियाबाद, गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 **मूल्य: ₹ 2 पेज: 06** विक्रमी संवत् 2081 **युगाब्द 5126 शाक 1946**

कैनडा बैंक Canada Bank

SCAN & PAY

UPI ID: 300012627000246@cnrb

BHIM UPI

Digitally signed by Anurag Singh, DN: cn=Anurag Singh, o=www.khabariya.com, email=anurag@khabariya.com

get online www.ncrmasala.com

NCR MASALA

India's Premium Masala

9410855900 ncrmasala@gmail.com

get online www.ncrmasala.com

गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

मुर्मु, मोदी और शाह ने डा. कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली * राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि श्रीमती मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में डॉ. अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ. कलाम को एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और राष्ट्र को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम का जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉ. कलाम की कल्पना के अनुरूप मजबूत, आत्मनिर्भर और करुणामय भारत का निर्माण जारी रखेंगे। श्री शाह ने डा. कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर नमन।'

दीपावली पर जगमगाएंगे दिव्यांगजन के हुनर के दीये

एनसीआर टुडे, लखनऊ *

उत्तर प्रदेश के घर-घर में इस दीपावली न केवल मिट्टी के दीये जलेंगे, बल्कि दिव्यांगजन के हुनर और आत्मनिर्भरता की चमक भी समाज को रोशन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंडलों में 16-17 अक्टूबर को 'दिव्य दीपावली मेला-2025' का आयोजन होगा। इसमें दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की भव्य प्रदर्शिनियां लगाई जाएंगी।

योगी सरकार की यह पहल न केवल 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र को साकार करने से साथ-साथ दिव्यांगजन को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान का नया मंच भी प्रदान करेगी। मिट्टी के दीपकों से लेकर कृत्रिम आभूषण और खाद्य सामग्री तक, इन प्रदर्शिनियों में दिव्यांगजन का कोशल दीपोत्सव की रौनक को दोगुना करेगा। योगी सरकार दिव्यांगजनों के न केवल आर्थिक समावेशिता को भी प्राथमिकता देती है। इस दीपावली, जब घर-घर दीये जलेंगे, तो दिव्यांगजन के हुनर की रोशनी पूरे प्रदेश को नई दिशा देगी।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में हस्तनिर्मित मिट्टी के दीपक, आकर्षक मोमबत्तियां, कृत्रिम आभूषण, हथकरघा उत्पाद, धरंलू



सजावटी सामान, पूजा सामग्री, आचार, मुंबवा, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री प्रदर्शित होंगी। ये उत्पाद विभिन्न दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ के सहयोग से तैयार किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी मंडल मुख्यालयों में प्रदर्शिनियों के लिए उचित स्थान चिह्नित करने और व्यापक प्रचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, दिव्यांगजन के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। यह पहल 'वोकल फॉर लोकल' के साथ दीपोत्सव को स्वदेशी रंग देने का प्रयास है। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ जैसे मंडलों में मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामचंद्र प्रसाद, अलयाघाट, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, बरेली आदि में भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक लोग इन प्रदर्शिनियों में शामिल हों और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। यह आयोजन दीपावली की रौनक को बढ़ाने के साथ-साथ समाज में संवेदनशीलता का संदेश देगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार ने दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। 'दिव्य दीपावली मेला-2025' का केवल उनके हुनर को मंच देना, बल्कि समाज को यह संदेश देना कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा से समाज को रोशन कर सकता है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब', पांच केंद्रों में AQI 300 के पार

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

दिल्ली के पांच निगरानी केंद्रों ने बुधवार को वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 300 से ऊपर चला गया। दिल्ली में 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं, जिनमें से 38 के आंकड़े उपलब्ध हैं।

आंकड़ों के अनुसार इनमें से पांच केंद्रों पर एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसमें आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई (345) दर्ज किया गया, इसके बाद डीयू नॉर्थ कैम्पस (307), सीआरआरआई मथुरा रोड (307), द्वाका सेक्टर 8 (314) और वकीरपुर (325) का स्थान रहा।

बुधवार को 20 केंद्रों ने एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि 13 केंद्रों ने 'मध्यम' श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया। डिजीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 201 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है। परिवहन उत्सर्जन प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जो कुल उत्सर्जन का 19.8 प्रतिशत था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'भयंकर' श्रेणी में माना जाता है।

हरित पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी



एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग को मंजूरी दिए जाने से पार्टी का यह रुख सही साबित हुआ है कि पिछली 'आप' (आम आदमी पार्टी) सरकार ने अदालत में ऐसे तर्क पेश किए थे जिनके कारण पटाखों पर प्रतिबंध लगा।

भाजपा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार की समातन धर्म के प्रति मंशा बेईमान थी।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ राजधानी में हरित पटाखों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी। अदालत ने कहा कि हरित पटाखों की बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक ही करने की अनुमति होगी और उनका उपयोग दीवाली से एक दिन पहले और दीवाली के दिन सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक किया जाएगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शीर्ष अदालत का यह फैसला उनकी पार्टी के रुख को सही साबित करता है।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'हम लंबे समय से कह रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे तर्क पेश किए जिनके कारण उच्चतम न्यायालय ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली की जनता ने अब सही सरकार चुनी है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं और वर्तमान सरकार उन्हें सुलझाने के लिए काम कर रही है। यह सनातनियों की जीत है।'

बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली * भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार को 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से मैदान में उतारा गया है। सूची के अनुसार, रामचंद्र प्रसाद अलयाघाट सीट से जबकि छोटी कुमारी और राकेश ओझा क्रमशः छपरा और शाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वीरेंद्र कुमार रोसड़ा और महेश पासवान अगिआंव सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सूची के अनुसार, रंजन कुमार मुजफ्फरपुर से और सुभाष सिंह गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे।

ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मिले राजनाथ, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली * भारत और ब्राजील ने रक्षा उपकरणों के सह-विकास तथा सह-उत्पादन के क्षेत्र एवं सेवाओं के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी व्यापक चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत यात्रा पर आए ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन और रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्लो के साथ बुधवार को यहां विस्तार से बातचीत की। श्री सिंह ने बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'आज नयी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन और ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्लो से मिलकर मुझे खुशी हुई। हमने सैन्य-से-सैन्य सहयोग और रक्षा-औद्योगिक सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर दूरदर्शी चर्चा की।'

NHRC ने राजकोट पुलिस हिरासत में नाबालिग को प्रताड़ित को लेकर डीजीपी को नोटिस भेजा

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली * राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने गुजरात पुलिस प्रमुख को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले महीने राजकोट जिले में पुलिस हिरासत में 17 वर्षीय किशोर को प्रताड़ित किया गया। एनएचआरसी ने बताया कि अधिष्ठित घटना छह अक्टूबर को तब सामने आई जब 'पिटार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया'। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने एक मीडिया में आई खबर पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि एक सितंबर को गुजरात के राजकोट जिले के गांधीग्राम पुलिस थाने में 17 वर्षीय लड़के को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत को चुनौती वाली याचिका में संशोधन की दी अनुमति

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत राजस्थान की जोधपुर के बजाय सजा के तौर पर घातक इंजेक्शन लगाने का विकल्प देना 'बहुत व्यावहारिक' नहीं हो सकता।

केंद्र की इस टिप्पणी के बाद न्यायालय ने कहा कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फांसी की सजा पाये दोषियों को फांसी देने के मौजूदा तरीके को कानून से हटाए जाने का अनुरोध किया गया था।

याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि कम से कम एक दोषी कैदी को यह विकल्प

हिरासत के आधारों को अब उचित रूप से चुनौती दी जा सके। उन्होंने पीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने की अनुमति नहीं है। श्री सिब्लल ने कहा, 'उन्होंने (वांगचुक) अपनी नजरबंदी पर कुछ नोट्स बनाए हैं, जिन्हें वह अधिवक्ता को देना चाहते हैं। वह जो भी नोट्स तैयार करते हैं, उसमें उन्हें वकील की सहायता लेने का अधिकार है। हम बस यही चाहते हैं कि नोट्स उन्हें दिए जाएं।' इस पर सिलिसिटर जनरल तृषार मेहता ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता, अंगमो के साथ नोट्स साझा किए जाने से कोई समस्या नहीं है। श्री मेहता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने हिरासत के आधार बताने में देरी।

बिहार चुनाव को लेकर मनी पावर और फ्रीबीज पर चुनाव आयोग की सख्त निगरानी, आदेश जारी

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव में धनबल, शराब, नशे और मुफ्त उपहारों (फ्रीबीज) के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

आयोग ने इस संबंध में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की थी। अब आयोग ने चुनाव खर्च और

अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की है।

चुनाव आयोग ने इस अभियान में कई एजेंसियों को शामिल किया है, जिनमें राज्य पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, एसएलबीसी, डीआरआई, सीबीएसटी, एसजीएसटी, कस्टम्स, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीसीएसए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डाक विभाग, वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग शामिल हैं। इन सभी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि

चुनाव के दौरान धन, शराब, ड्रग्स या अन्य प्रलोभनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके।

आयोग ने चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात कर दिया है। ये अधिकारी अधिसूचना जारी होते ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच गए हैं और वहां व्यय निगरानी से जुड़ी टीमों से मिलकर समन्वय कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि फ्लाईंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमों और वीडियो मॉनिटरिंग टीमों चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

जुबिन के परिजनों से मुलाकात करने असम जाएंगे राहुल गांधी

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के परिजनों से मुलाकात करने शुक्रवार को असम जायेंगे।

गौरतलब है कि लोकप्रिय असमिया गायक की 19 सितंबर को सिंगापुर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुयी थी।

वह सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। घटना के बाद असम सरकार ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए थे और हत्या की साजिश के शक के चलते कई प्राथमिकी दर्ज कर सीआईडी की जांच सौंपी गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गांधी शुक्रवार को गायक के परिजनों से मुलाकात करने असम जायेंगे। जुबिन की रहस्यमयी मौत के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है।

पार्टी की तरफ से असम में इस मुसले पर विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस भी निकाला गया है। पार्टी की मांग है कि गायक की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की जाये।

असम कांग्रेस प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में इस मामले में भाजपा के बयानों से साफ हो गया है कि उन्होंने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है।

उनके बयानों में अब कोई मर्यादा नहीं बची है। दिवंगत गायक पर सवाल उठाना और पुलिस के जरिए बल प्रयोग करना दिखाता है कि सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है।'

उन्होंने कहा कि जुबिन की मौत के बाद लोग अभी भी गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार उनकी मौत से जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी।

लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जुबिन की मौत के बाद भी सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कैसे जारी रहा।

आधार अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों ने घातक इंजेक्शन को अपनाया

केंद्र ने फांसी की सजा के तौर पर घातक इंजेक्शन के इस्तेमाल का समर्थन नहीं किया: सुप्रीम कोर्ट

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों को फांसी के बजाय सजा के तौर पर घातक इंजेक्शन लगाने का विकल्प देना 'बहुत व्यावहारिक' नहीं हो सकता।

केंद्र की इस टिप्पणी के बाद न्यायालय ने कहा कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फांसी की सजा पाये दोषियों को फांसी देने के मौजूदा तरीके को कानून से हटाए जाने का अनुरोध किया गया था।

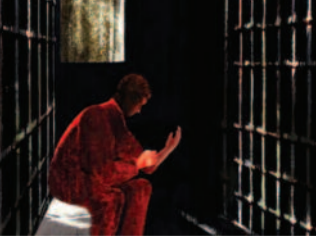
याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि कम से कम एक दोषी कैदी को यह विकल्प

दिया जाना चाहिए कि वह फांसी चाहता है या घातक इंजेक्शन।

मल्होत्रा ने कहा, 'सबसे अच्छा तरीका घातक इंजेक्शन है, क्योंकि अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों ने घातक इंजेक्शन को अपना लिया है।' उन्होंने कहा कि घातक इंजेक्शन लगाने का विकल्प देना त्वरित, मानवीय और सभ्य है, जबकि फांसी देना क्रूर और बर्बर है, क्योंकि इसमें शव लगभग 40 मिनट तक रस्सी पर लटका रहता है।

न्यायमूर्ति मेहता ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को सुझाव दिया कि वह मृत्युदंड की सजा पाये दोषी को विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में मल्होत्रा के प्रस्ताव पर सरकार को सलाह दें।

केंद्र के वकील ने कहा, 'इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि यह विकल्प देना



बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकता है।'

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, 'समस्या यह है कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है... समय के साथ चीजें बदल गई हैं।' केंद्र के वकील ने दलील दी कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यह एक नीतिगत फैसला है और सरकार इस पर फैसला ले सकती है।

वकील ने इस मामले में उच्चतम

न्यायालय द्वारा मई 2023 में पारित आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में, पीठ ने अर्दानी जनरल आर. वेंकटरमणी की उस दलील पर गौर किया था कि सरकार इस मामले में उठाए जाने वाले मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति की नियुक्ति पर विचार कर रही है। केंद्र के वकील ने कहा कि वे सरकार से निर्देश लेंगे कि समिति के संबंध में प्रोटेक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीसीएसए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डाक विभाग, वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग शामिल हैं। इन सभी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह विधायिका को दोषी ठहराए गए लोगों को सजा देने का कोई विशेष तरीका अपनाकर का निर्देश नहीं दे सकती।

मल्होत्रा ने 2017 में जनाहित याचिका दायर कर फांसी पर लटकाकर मौत की सजा देने की मौजूदा प्रथा को समाप्त करने और इसके स्थान पर 'अंतःशिरा घातक इंजेक्शन, गोली मारना, बिजली का झटका देना या गैस चैंबर' जैसे कम दर्दनाक तरीकों को अपनाये जाने का अनुरोध किया था। केंद्र ने 2018 में इस कानूनी प्रावधान का पुरजोर समर्थन किया था कि मौत की सजा पाए दोषी को केवल फांसी पर लटकाया जायेगा और पीठ को बताया था कि घातक इंजेक्शन देकर और गोली मारने जैसे मृत्युदंड के अन्य तरीके भी कम दर्दनाक नहीं हैं।

बनारस में लाल मिर्च, बुंदेलखंड में मूंगफली, बाराबंकी से आजमगढ़ तक केले का क्लस्टर तैयार होगा:योगी

बनारस, एजेंसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 'कमोडिटी क्लस्टर' दृष्टिकोण के तहत बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी से आजमगढ़ के बीच केला, कालानमक चावल, हरी मटर, उड़द और आलू आदि के क्लस्टर विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'टिशू कल्चर' को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेक्टरल विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री मंगलवार को उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट (यूपी एपीज) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में 'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम' के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाए, जो राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित हो और सुरक्षित साइबर अवसरकता तथा नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक की प्रक्रिया को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ते हुए यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण

उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य के कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत एवं डिजिटल टिकाऊ कृषि तंत्र की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कृषि से उद्योग तक' की सोच के साथ कार्य करते हुए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाए। निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना (यूपी ड्रास्प) के समन्वयन में यूपी एपीज का क्रियान्वयन करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को भी परियोजना से जोड़ा जाए।

बैठक में बताया गया कि यह परियोजना लगभग 4000 करोड़ (यूएस 500 मिलियन) की लागत से विश्व बैंक के सहयोग से छह वर्षों की अवधि के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जनपदों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुरूप कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि करना और किसानों को बाजार से बेहतर रूप में जोड़ना है। परियोजना में उत्पादकता वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृषि विद्यया प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण सुविधा, जोखिम प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था और निजी निवेश को प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। बैठक में बताया गया कि परियोजना से संबंधित संस्थागत तैयारियों में ठोस प्रगति हुई है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। मॉनिटरिंग, लॉनिंग एवं इवैल्यूएशन एजेंसी तथा तकनीकी सहायता एजेंसी का चयन किया जा चुका है।

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) के साथ छह वर्षीय उत्पादकता कार्यक्रम के लिए अनुबंध स्वीकृत हो चुका है। किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा, जबकि तकनीकी परामर्शी एजेंसी का चयन अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के प्रत्येक घटक के परिणामों की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यूपी एपीज की सतत मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए।

संक्षिप्त समाचार जबलपुर में बढ़ रहे अचानक हार्ट अटैक के मामले

जबलपुर। डॉ. आर.एस. शर्मा, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी (एम्स नई दिल्ली) ने बताया, शादी समारोहों, गरबा नाइट्स, जिम और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाचते या व्यायाम करते हुए अचानक गिरने वाले युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जबलपुर शहर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पूरी तरह स्वस्थ दिखने वाले लोग कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि सडन कार्डियक अरेस्ट (अचानक हृदय रुक जाना) का बढ़ता खतरा है। शलबी हॉस्पिटल और एस.एस. मेडिकल कॉलेज,जबलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसे मरीजों के दिल में अक्सर पहले से ब्लॉकज या इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी होती है, जो समय पर जांच न होने से पता नहीं चलती। जब वे अचानक नाचते या व्यायाम करते हैं तो हृदय पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल रुक जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि जबलपुर की बदलती जीवनशैली ने स्थिति को और खराब कर दिया है। पौष्टिक पर का खाना अब तैलीय और पैकेटबंद फास्ट फूड ने ले लिया है। जरूरत से ज्यादा खाना, बार-बार स्लैकिंग, और फल-सब्जियों की कमी ने शरीर में पोषण अस्तंतुलन पैदा कर दिया है। धूम्रपान, तनाव और नींद की कमी ने दिल को और कमजोर बना दिया है। डॉ. आर.एस. शर्मा, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी (एम्स नई दिल्ली) के अनुसार चिंता की बात यह भी है कि कई लोग वॉर्क नैचिग रहने के बाद अचानक भारी व्यायाम या जिम शुरू कर देते हैं। डॉ. शर्मा ने कहा, बिना जांच कराए अचानक भारी एक्सरसाइज करना खतरनाक है।

रोमांस बनेगा मैक्स का स्पोर्ट्स लाइट!

भोपाल, एजेंसी। संगीतमय प्रेम कहानियाँ सिनेमा की दुनिया में बेहद दुर्लभ होती हैं – जो दिल को छू जाने वाले रोमांस को आत्मा को झूकृत कर देने वाले संगीत से इस तरह जोड़ती हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके एहसास मन में गुंजते रहते हैं। अनुराग बसु के निर्देशन में यह फिल्म सिर्फ प्रेम कहानियाँ नहीं सुनाती, बल्कि उन्हें महसूस करवाती है – और इसी वजह से यह अपने जान्ार की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार हो चुकी है। सोनी मैक्स लेकर आ रहा है यह अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव – मेट्रो इन् दिनों का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर – रविवार, 19 अक्टूबर रात 8 बजे। मेट्रो इन् दिनों अनुराग बसु की लाइफ इन् अज् मेट्रो का सीकल है, जो ह्यूपरकैलिब्र नैरेटिव के जरिए भारत के शहरी जीवन में रिश्तों की पेचीदगियों को बारीकी से दिखाती है। फिल्म को इसके संवेदनशील लेखन, शानदार एंसेंबल कास्ट और भावनाओं से भरे संगीत के लिए जबरदस्त सराहना मिली है। आलोचकों ने फंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल, पंकजिा सना शेख, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के अभिनय की खूब तारीफ की है – सभी ने प्रेम, विद्योग और मोक्ष की जुड़ी हुई कहानियों को सच्चाई और गहराई से पेश किया है। अनुराग बसु का निर्देशन और प्रीतम का आत्मीय संगीत फिल्म की इमोशनल हार्टबीट कहलाया है, जो दर्शकों के दिल में लंबे समय तक गुंजाता रहता है। यह फिल्म आज के दौर के मुद्दों – जैसे डेटिंग ऐप कल्चर, करियर का दबाव और रिश्तों में समझौते – पर रोशनी डालती है और दिखाती है कि तेज रफ्तार शहरी जीवन में लोग प्रेम और अव्यवस्था के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं।

विशेष बिहार चुनाव में इसबार भी हावी रहेगी जाति आधारित राजनीति



बेरोजगारी और पलायन युवाओं को प्रभावित कर रहे, जबकि जाति और वोट लिस्ट विवाद पारंपरिक वोट बैंकों को प्रभावित कर सकते हैं। राजग विकास और सुरासन पर जोर दे रही, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) " सामाजिक न्याय" और "नौकरी" के वादे पर जोर दे रहा जबकि जन सुराज नया विकल्प बनने की कोशिश में है। बिहार के लिए सबसे बड़े पर्व छठ पूजा के बाद 6 और 11 नवंबर की वोटिंग में टनआउट और ग्रांडड मूड निर्णायक होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई प्रमुख मुद्दे मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ये मुद्दे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों से जुड़े हैं और बिहार की ग्रांडड रियलिटी को दर्शाते हैं। बिहार में बेरोजगारी एक दीर्घकालिक और गंभीर है। 2023-24 के डेटा के अनुसार, बिहार में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत (3.2 प्रतिशत) से दोगुनी है। युवा (15-29 आयु वर्ग) में बेरोजगारी 13-15

खराब सड़कों के लिए बहाना नहीं चलेगा

● अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने ना केवल बाध्य हैं, बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है

मुंबई , एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में खराब सड़कों को कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी और सरकारें, नागरिकों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ना केवल बाध्य हैं, बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने गड्डों और खुले मैनेहोल के कारण हुई मौतों के मामले में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। वहीं चोटों के मामलों में 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच का मुआवजा देना होगा। जस्टिस रेवती मोहिते हुए और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ ने इस तरह की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गड्डों, खुले मैनेहोल और खराब सड़कों के कारण मौतें और दुष्टटनाएं आम बात हैं और इसलिए संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने



कहा, अब समय आ गया है कि गड्डों के कारण हुई मौतों या उनकी वजह से घायल होने वाले पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तभी यह संबंधित एजेंसियों के लिए एक चेतावनी होगी।

जब तक अपनी जेब से अदालत ने आगे कहा कि जब तक गड्डों से होने वाली मौतों और चोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को

अदालत ने कहा, खराब और असुरक्षित सड़कों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, मुंबई केंद्र, राज्य और नगर निकाय के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एनसीजीएम एशिया के सबसे धनी निगमों में से एक है। खराब सड़कें न केवल मानव जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति सहित अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

अनुच्छेद 21 का जिक्र: इस दौरान कोर्ट ने दोहराया कि अच्छी और सुरक्षित सड़कें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। कोर्ट ने कहा, टेक्स देने वाली जनता को सुरक्षित सड़कों सहित उचित नागरिक सुविधाएं प्रदान करना नागरिक अधिकारियों और राज्य एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र में जनवरी 2026 तक ना हो एसआईआर, ईसीआई के पास पहुंची अर्जी

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एमईसी) ने हाल ही में चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। एमईसी ने कहा है कि इस अगर आयोग की ऐसी कोई योजना है तो उसे जनवरी 2026 तक स्थगित किया दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग बीते 9 सितंबर को आयोग को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि राज्य के अधिकारी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त रहेंगे और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। एमईसी ने कहा, "भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चार महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में समय विस्तार की मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।" राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि स्टूड्रक और स्थानीय निकाय चुनाव कराने वाले अधिकारी एक ही होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निर्माों के 247 नगर परिषदों, 147 नगर परिषदों में से 42 नगर पंचायतों, 34 जिला परिषदों में से 32 और 351 पंचायत समितियों में से 336 के लिए चुनाव होने हैं। इन सभी निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से जनवरी 2026 तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार (जिन्हें

स्थानीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है) इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा, "चूँकि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सहित क्षेत्रीय कर्मचारी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक ही अधिकारी हैं, इसलिए अनुरोध है कि अगर आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है तो उसे कम से कम जनवरी 2026 के अंत तक स्थगित कर दिया जाए।"

इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह में जनवरी 2026 तक एसआईआर आयोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

पुलिस का एक्शन, एनकाउंटर के बाद चेन सैचर नौशाद गिरफ्तार

गाजियाबाद, एजेंसी। गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद चेन सैचर नौशाद उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से दो सोने की चेन, 48 हजार रुपये नकद, एक तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। यह घटना ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के नीचे हुई, जहां मुरादनगर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। दुहाई गांव की तरफ से आ रही बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन सवार युवक नहीं रुका और कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गया। गड्डों के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह फिसलकर गिर गई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने का प्रयास करने पर युवक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश नौशाद उर्फ बादशाह (उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी फरुखनगर, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद) के पैर में गोली लग गई। पृष्ठताछ में सामने आया कि नौशाद अपने एक साथी के साथ मिलकर कुछ महीने पहले मौदीनगर से एक पलैट से ज्वेलरी और नकदी चोरी कर चुका है। उसने सितंबर माह में मुरादनगर क्षेत्र से और भगवान महावीर मार्ग, बड़ोत, बागपत से भी चेन सैचर की वारदातों को अंजाम दिया था। बरामद मोटरसाइकिल भी कुछ साल पहले साहिबाबाद थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। गिरफ्तार बदमाश डासना की तरफ बरामद सामान बेचने की फिराक में जा रहा था।



शहर के 852 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे एनपीआर कैमरे, पुरानी गाड़ियों की होगी निगरानी

गुरुग्राम , एजेंसी। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से पहले चरण में चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में एनपीआर में आने वाले सभी जिलों में यह काम शुरू होगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान होगी। एनपीआर कैमरे लगाने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन की पहचान पंप के



प्रवेश पाइंट पर होगी। सॉफ्टवेयर की मदद से संबंधित वाहन को पूरी जानकारी मिलेगी। यदि वाहन 10 व 15 साल पुराने हो गए हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल से इनकार कर दिया जाएगा। पंपों पर ऐसे काम करेगा कैमरा : कैमरे वाहनों के नंबर प्लेटों को ऑटोमैटिक रूप से पहचानने और पढ़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कैमरे ऑप्टिकल कैरेक्टर

(अक्षर और संख्याएं) को पहचनेगा। पहचाने गए नंबर प्लेट डेटा को एक डेटाबेस से मिलाया जाता है, जिसमें वाहन के मालिक, रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारी होती है। इस डेटा का उपयोग कार ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, टोल कलेक्शन और क्राइम का पता लगाना जाएगा। जिला परिवहन विभाग के अनुसार, हरियाणा सरकार की ओर से ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा (एनपीआर) खरीदने की हो चुकी है। कैमरों की खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री ऑफिस में भेजी है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ही परिवहन विभाग एनपीआर कैमरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।

डाबर रियल जूस ने 'रियल ग्रीटिंग्स दिवाली गिफ्ट पैक्स' की एक विस्तृत श्रृंखला लॉन्च की

एनसीआर टुडे. कानपुर। जैसे-जैसे रोशनी का त्योहार दिवाली नजदीक आ रहा है, भारत के प्रमुख जूस ब्रांड, डाबर इंडिया लिमिटेड के रियल फ्रूट जूस ने 'रियल ग्रीटिंग्स दिवाली गिफ्ट पैक्स' की एक बड़ी रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। रियल के ये खास गिफ्ट पैक बजट के अनुकूल हैं और इनकी कीमत ₹93 से लेकर ₹506 के बीच है। इनका उद्देश्य फलों की अच्छाई के साथ 'स्वस्थ त्योहारी शुभकामनाएं' देना है, जो स्वास्थ्य और खुशी के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को दिखाता है। डाबर इंडिया लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) श्री मयंक कुमार ने कहा, "दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है जब परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। दिवाली के दौरान उपहारों का आदान-प्रदान सबसे पसंदीदा परंपरा है। त्योहार पर शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के लिए लोगों को एक स्वस्थ विकल्प देने के लिए, हमने रियल फ्रूट बेवरेज के 19 विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'रियल ग्रीटिंग्स दिवाली गिफ्ट पैक्स' लॉन्च किए हैं। फलों की असली अच्छाई से भरपूर, ये गिफ्ट पैक स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल प्रदान करते हैं। इन गिफ्ट पैक्स के जरिए, हम उपभोक्ताओं को इस त्योहारी सीजन में अपने प्रियजनों को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने का एक माध्यम दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि लोग इन गिफ्ट पैक्स को पसंद करेंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल दिवाली मनाने के लिए इनका आदान-प्रदान करेंगे।" रियल दिवाली ग्रीटिंग्स गिफ्ट पैक्स में शामिल हैं: बुक पैक ₹417, बॉक्स पैक ₹107, बकेट पैक ₹506, हैंडल पैक ₹131, जूट बैग 3 लीटर ₹403, पीवीसी 3 लीटर ₹392, पीवीसी बैग 2 लीटर ₹248, रियल कूलर्स गिफ्ट पैक ₹93, रियल मिनी पैक ₹93, विटामिन बूस्ट पैक 3 लीटर ₹467।



संपादकीय

क्या यही है ‘संघ’ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सच्चाई ?

2 अक्टूबर यानी विजय दशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गये। संघ की स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में विजय दशमी के दिन राष्ट्र निर्माण और सामाजिक ज़म्मेदारी के ‘घोषित उद्देश्य’ से की गयी थी। संगठन की स्थापना के समय यही बताया गया था कि संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसका उद्देश्य देशवासियों में संस्कृति के प्रति जागरूकता, अनुशासन, नैयता और सामाजिक ज़म्मेदारी की भावना को बढ़ाना है। शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर देश भर में अनेक आयोजन हुये जिसमें संघ का गुणगान किया गया।

संघ समर्थक सत्ताधारियों द्वारा जो का क्रसीदा पढ़ने वाले अनेक लेख लिखे गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघि स्वयं की सभ प्रचारक रह चुके हैं, ने राष्ट्र निर्माण में आर एस एस के योगदान की सराहना की। मोदी ने संघ के शताब्दी समारोह में कहा कि -‘संघ ने पिछली एक सदी में अनीतानि जीवनकों को दिशा दी और मजबूत बनाया। जिस तरह सभ्यताएँ महान नदियों के किनारे विकसित होती हैं, उसी तरह संघ की धारा के साथ सैकड़ों जीवन खिले और आगे बढ़े हैं।’

RSS का उद्देश्य हमेशा एक ही रहा राष्ट्र निर्माण।’ इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा संघ के नाम पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गये। संघ के लोग इसे विश्व का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन बताते हैं। आज देशभर में लाखों स्वयंसेवकों के माध्यम से संघ अपने ‘घोषित व अघोषित’ कार्यों में सक्रिय है। परन्तु यह भी सच है कि स्थापना के समय से ही अनेक सदस्यों द्वारा उसके साथ बार-बार किये गये यौन शोषण पर संस्था के रजिस्टर्ड संस्था न होने के साथ साथ इस पर साम्प्रदायिकता फैलाने व धर्म जाति के आधार पर नफ़रत फैलाने का भी आरोप लगाता रहा है। देश का एक बड़ा वर्ग महात्मा गाँधी की हत्या में संघ की साम्प्रदायिक विचारधारा को भी ज़म्मेदार मानता है। इस बात के भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि बापू की हत्या के बाद संघ कार्यालय में जरन मनाया गया था और मिठाइयां बाँटी गयीं थीं। देश के विभाजन से लेकर आज तक देश में हुये अनेकानेक साम्प्रदायिक दंगों में संघ के कार्यकर्ता आरोपित रहे हैं।

इतना ही नहीं बल्कि संघ के अनेक कार्यकर्ताओं पर चरित्रहीन होने,बलात्कार व बाल व्यभिचारी होने तक के आरोप लगते रहे हैं। और इसे भी अजीब संयोग समझा जाना चाहिये कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जब संघ,सत्ता व भाजपा संघ के शताब्दी वर्ष के जरन में डूबे हुये हैं इसी दौरान संघ द्वारा संचालित शाखाओं में जहां बच्चे ‘संस्कार’ के नाम पर भेजे जाते हैं,केरल के एक युवक द्वारा संघ व इसके अनेक सदस्यों द्वारा उसके साथ बार-बार किये गये यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर लेने जैसे क्रक्रम ने संघ के वास्तविक चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है। केरल के कोट्टयम ज़िले के एलिकुलम निवासी 26 वर्षीय आईटी प्रोफ़ेशनल युवक, अर्न्तु आजी ने 9 अक्टूबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के थंगानूर स्थित एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली।

अर्न्तु आजी की आत्महत्या के बाद उनके द्वारा मलयालम भाषा में लिखा गया 7 से 15 पेज लंबा सुसाइड नोट सार्वजनिक हुआ। इस नोट में अर्न्तु ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के सदस्यों द्वारा बचपन से उसके साथ लगातार किये जा रहे यौन शोषण और बलात्कार का ज़क्रि है।

मलयालम भाषा में सुसाइड से पूर्व लिखा गया उसका अंतिम पत्र अथवा सन्देश संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ के मुँह पर कालिख पोंतन का काम कर रहा है। 26 वर्षीय आईटी प्रोफ़ेशनल युवक सुसाइड से पूर्व लिखे गये अपने अंतिम नोट में लिखता है कि -- ‘मैं अर्न्तु आजी हूँ, कोट्टयम के थम्पल काड से। मैं हमेशा से ही एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति रहा हूँ। लेकिन बचपन से ही मुझे जो दर्द सहना पड़ा, उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मैं अपनी ज़ाँदियाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि एंग्यज़ायटी और लगातार पैनिक अटैक ने मुझे जीना मुश्किल बना दिया है।

यह ट्रॉमा का नतीजा है जो मुझे 4 साल की उम्र से सता रहा है। मुझे 4 साल की उम्र से ही एक पड़ोसी व्यक्ति द्वारा लगातार यौन शोषण का शिकार बनाया गया। वह मेरे परिवार के करीब था और मुझे धमकाता था। यह शोषण सालों तक चला। मैं एक रेप विक्टिम हूँ। बचपन में ही मेरी मासूमियत छीन ली गई। मेरे पिता ने मुझे 3-4 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल करा दिया। मैं शाखा और कैम्पों में जाता रहा। वहां मुझे कई आरएसएस सदस्यों के द्वारा यौन शोषण और बलात्कार का सामना करना पड़ा। मैं नामित करता हूँ ‘एन.एम.’ को, जो आरएसएस और भाजपा का प्रमुख सदस्य है। उसने मुझे कई बार शोषित किया, ख़ासकर कैम्पों के दौरान। मैं अकेला नहीं हूँ—कई अन्य लड़कें भी इसी तरह के दोहन के शिकार हुए हैं। आरएसएस कैम्पों में यह एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आरएसएस के कई सदस्यों ने मुझे छुआ, शोषित किया। मैं उनके नाम नहीं जानता क्योंकि डर के मारे चेहरा भी याद नहीं। लेकिन एन.एम. का नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह मेरे लिए एक भयानक स्मृति है।

अर्न्तु आजी आगे लिखते हैं कि -‘इन घटनाओं का नाम डिप्रेशन और एंग्यज़ायटी का मरीज बना दिया। मैं थैरेपी ले रहा था, लेकिन ट्रामा इतना गहरा था कि मैं रोज़ पैनिक अटैक से जूझता। बचपन का दर्द मुझे कभी शांति नहीं देता। मैंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हार मान ली।’ मेरी माता-पिता को दोष न दें। उन्होंने मुझे अच्छा जीवन दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। मैंने कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि डर था। समाज को पता चलना चाहिए कि ऐसे संगठनों में बच्चे सुरक्षित नहीं। लाखों बच्चे शाखाओं में जाते हैं—कुछ को बचाना जरूरी है।’ अंत में वे लिखते हैं कि -‘मैं अपनी मौत के लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। कृपया जांच करें और दैतियों को सजा दें। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो।’ मैं थक गया हूँ, अब विदा हो रहा हूँ। कृपया मेरी कहानी को दबाएँ नहीं। अलविदा।’ अर्न्तु ने अर्न्तु आजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के जयन्त दिवस पर आईटी प्रोफ़ेशनल युवक द्वारा संगठन के लोगों पर अति गंभीर आरोप लगाते हुये आत्महत्या तक कर लेना निश्चित रूप से यह सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि क्या यही है संघ के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की सच्चाई ?

गाजियाबाद, गुरुवार 16 अक्टूबर 2025

इस्त्राइल-हमास युद्धविराम: किरण या अस्थायी विराम?

ललित गर्ग

गाजा की धरती लम्बे दौर से संघर्ष, हिंसा, विनाश और तबाही की त्रासदी की गवाह रही है, आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ शांति की एक हल्की किरण दिखाई तो देती है, परंतु उसके चारों ओर धुँएँ और राख का अंधकार अब भी विद्यमान है। हाल ही में हुए युद्ध-विराम ने न केवल मध्यपूर्व बल्कि समूचे विश्व को राहत की एक साँस दी है। गाजा में अमन-चैन की ओर जो सुखद कदम बढ़े हैं, उनका स्वागत होना चाहिए।

परंतु यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या यह शांति स्थायी होगी, या यह केवल अगली लड़ाई से पहले का ठहराव भर है? समूची दुनिया चाहती है कि यह युद्ध विराम स्थायी हो क्योंकि इस्त्राइल और हमास के संघर्ष ने करीब बाइस लाख से अधिक लोगों को बेघर करके भुखमरी के कगार पर खड़ा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिये समझौते के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करना बेहद जरूरी होगा।

जिसमें बंधकों व कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को अनवरत जारी रखना और इस्त्राइली सेनाओं की गाजा के मुख्य शहरों से आंशिक वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह सब दूसरे चरण की बातचीत पर निर्भर हैं। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसके बाद ही दूसरे चरण की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बेहद मुश्किल चुनौतियाँ वाला चरण होगा। इस दौरान कई संवेदनशील मुद्दे सामने होंगे।

सबकी निगाह इस पर होगी कि शांति समझौते के अगले चरण कब पूरे होते हैं और वे सच्ची तरह पूरे होते भी हैं या नहीं? इस पर संशय इसलिए है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कि इजरायली सेना गाजा में कितना पीछे हटेंगी और वहां के प्रशासन को संचालित करने का कैसा तंत्र तैयार होगा और क्या उस पर हमास सहमत होगा? इसके अतिरिक्त जहां हमास को हथियार छोड़ने हैं, वहीं इजरायल को स्वतंत्र फिलस्तीन

देश को राह आसान करनी है। हमास का कहना है कि हथियार तब छोड़े जाएंगे, जब स्वतंत्र फिलस्तीन का रास्ता साफ होगा। इस पर इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि स्वयं की ओर से प्रशंतावित गाजा शांति समझौते पर अमल शुरू होने के अवसर पर, मिश्र जाने के पहले इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहल को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना का पथ करार दिया और इजरायली प्रधानमंत्री से ईरान से समझौता करने को कहा। ऐसे किसी समझौते की सूरत तब बनेगी, जब ईरान इजरायल को मिटाने की अपनी जिद छोड़ेगा।

गाजा की वर्तमान स्थिति किसी एक राष्ट्र या एक नीति की देन नहीं है; यह दशकों से चली आ रही अविश्वास, असमानता और राजनीतिक स्वार्थों की परिणति है। इस बार के संघर्ष ने जिस तरह से निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध चाहे किसी भी नाम पर लड़ा जाए, उसका परिणाम हमेशा मानवीय त्रासदी ही होता है।

अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल-कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने आधिकारक शेष जीवित बचे बीस इस्त्राइली बंधकों को रिहा कर दिया। जिसके बाद इस्त्राइल में किसी बड़े उत्सव जैसा जश्न दिखा। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्त्राइल-हमास जोखिमभरा युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर एवं ईमानदार प्रयास लगातार होते रहें।

वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती भूतहा खण्डहर एवं तबाही में तब्दील हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण की होगी। दो साल से लगातार जारी युद्ध के चलते यह इलाका मलबे के ढेर में

हरियाणा को बचाना है, तो नफरत को हराना होगा

डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है। एक नहीं, दो पुलिसकर्मियों की आत्महत्याएँ हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच-नीतों पर सवाल उठा रही हैं। इंसाफ़ का रास्ता जब लोगों को बंद दिखाई देता है, तो वे जिंदगी से भी हार मान लेते हैं। यह सिर्फ़ दो जवानों की मौत नहीं, बल्कि उस तंत्र की पराजय है, जिस पर नागरिक भरोसा करते हैं। आज जब चारों ओर गुस्सा, अफ़वाहें और जातीय बहस हैं, तब सबसे जरूरी है संयम और समझ। क्योंकि अगर समाज भावनाओं में बह गया, तो यह सिर्फ़ दो परिवारों की त्रासदी नहीं रहेगी, बल्कि हरियाणा का सामाजिक ताना-बाना टूट जाएगा।

दोनों आत्महत्याएँ दिल को झकझोर देने वाली हैं। आईपीएस पूरन कुमार की मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, और फिर एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने इस दर्द को और गहरा कर दिया। दोनों ने अपने बीडियो या संदेशों में जो दर्द व्यक्त किया, वह किसी जातीय नफ़रत का परिणाम नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति मोहभंग का परिणाम था जिसमें उन्हें इंसाफ़ का रास्ता दिखाई नहीं दिया।

हर आत्महत्या एक चीख़ होती है-ऐसी चीख़ जो कहती है कि ‘सुनो, अब ओर नहीं!’ और जब सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग खुद अपनी जान दे देते हैं, तो यह संकेत होता है कि भीतर कुछ बहुत गंभीर रूप से सड़ चुका है।

आज सोशल मीडिया और राजनीति दोनों इस मामले को जातीय चरम से देखने में लगे हैं। कोई इसे एक जाति बनाम दूसरी जाति के संघर्ष की तरह दिखा रहा है, तो कोई इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है-यह दो जातियों की नहीं, दो इंसानों की त्रासदी है।

पूरन कुमार और संदीप लाठर, दोनों ही अपने-अपने परिवारों, अपने-अपने समाजों और अपनी-अपनी ड्यूटी के लिए समर्पित थे। दोनों का उद्देश्य था न्याय और आत्मसम्मान।



परंतु जब व्यवस्था में उन्हें विश्वास नहीं मिला, तो उन्होंने वह रास्ता चुना, जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए सबसे दर्दनाक होता है।

हमें समझना होगा कि अगर हम इन घटनाओं को जातीय बहस में बदल देंगे, तो असली मुद्दा-व्यवस्था में गिरता विश्वास-हमेशा के लिए दब जाएगा। ऐसा करना न केवल इन आत्महत्याओं की पीड़ा का अपमान होगा, बल्कि यह समाज को और गहरे अंधकार में धकेल देगा।

हर आत्महत्या के पीछे एक कहानी होती है-कभी चूप रह जाने की, कभी आवाज न सुने जाने की, और कभी अन्याय से लड़ते-लड़ते थक जाने की। पूरन कुमार और संदीप लाठर की मौतें इसी थकान का परिणाम हैं। दोनों के पास शायद अभी बहुत वक्त था, बहुत संभावनाएँ थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी उस वक्त खत्म की जब उन्हें लगा कि अब उन्हें इंसाफ़ का रास्ता दिखाई नहीं दिया।

यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है-जब कोई नागरिक यह मान ले कि व्यवस्था अब उसकी रक्षा नहीं बनी। और जब लोग न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं, तब समाज अराजकता की ओर बढ़ता है।

इतिहास गवाह है कि जब भी समाज ने नफरत के रास्ते पर चलना शुरू किया, उसने खुद को कमजोर किया। चाहे वह धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो या जाति के नाम पर-अंत में नुकसान हर बार समाज को ही हुआ लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है-यह दो जातीय उत्क्राव की शकल देते, तो हम फिर उसी पुराने गढ़ में गिर जाएंगे, जिससे निकलने में हमें दसकों लीगों। नफरत का जवाब नफरत ही हो सकता। इसका जवाब है-संवाद, सुधार और सहानुभूति।

संपादकीय

इस्त्राइल-हमास युद्धविराम: किरण या अस्थायी विराम?



तब्दील हो चुका है।

एक नाजुक समय में जब युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि मानवीय विवेक का पुनर्जागरण भी है। यह समझना आवश्यक है कि शांति कोई समझौता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि यह युद्धविराम पूरी मानवता के लिए एक ‘आशा की किरण’ बनकर उभरा है।

यह उस संभार का प्रतीक है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, और अरब राष्ट्र अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर मानवीय सरोकारों को महत्व देते हैं, तो समाधान की दिशा में रास्ता बनता है। फिर भी इस शांति की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस युद्धविराम को अपने कूटनीतिक प्रयासों की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हो, पर सच यह है कि युद्ध तब रुका जब उसकी भयावहता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यह विराम किसी की “कूटनीति की जीत” से अधिक, मानवीय विवशता की उपज है।



दोनों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मानवीय संगठनों की सक्रियता और आम नागरिकों की पुकार ने मिलकर इस विराम को संभव बनाया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह शांति टिके, युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला फैले।

क्योंकि जब तक गाजा के लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएँ-पानी, भोजन, दवा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलते, तब तक शांति केवल कागज़ों पर दर्ज रहेगी। वास्तविक शांति केवल तब संभव है जब अन्याय, दमन और असमानता के ढाँचे टूटें। शांति का अर्थ केवल हथियारों का मौन नहीं, बल्कि हृदयों का परिवर्तन है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए गाजा शांति समझौते को पश्चिम एशिया का ऐतिहासिक मुबह की संज्ञा दी। वे कुछ भी दावा करें, फिलहाल यह कहना कठिन है कि प्रमुख मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे।

भले ही ट्रंप यह कह रहे हों कि गाजा शांति समझौते को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, लेकिन वस्तुस्थिति इससे अलग है। जब यह समझौता सामने आया था, तब उसे समर्थन

से मुक्त हो। संवेदनशील नेतृत्व सामने आए जो केवल बयान न दे, बल्कि संस्थागत सुधार करें। मीडिया जिम्मेदारी निभाए जो सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाएं। और समाज संयम रखे जो अफवाहों और जातीय टिप्पणियों से दूर रहे। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक गलत फैसले से वह पल में टूट जाता है। अब समय है उसे फिर से जोड़ने का। हर न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में सुनने को आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएँ, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें ऐसे समाज कि निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समझौता में

एमए प्रथम वर्ष की छात्रा बनी मिस फ्रेशर

★ एनसीआर टुडे, अलीगढ़ ★

टीकाराम कन्या महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा एमए की छात्राओं हेतु फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। एमए प्रथम वर्ष की छात्राओं में से कुमारी डॉली को मिस फ्रेशर चुना गया।

छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गएस कुमारी नेहा चौधरी एमए प्रथम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने कहा की छात्राएं महाविद्यालय रत्न पर ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय रत्न पर भी अपना नाम रोशन करें। इस अवसर पर सकुमारी वैष्णवी राजोरिया, स्नेह लता, हनी, ज्योति चौधरी, बुलबुल, पायल, दीपांशी, प्रानेश आदि छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विभाग प्रभारी प्रोफेसर सपना सिंह के निदेशन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन अस्मिस्ट प्रोफेसर डॉ. नीलम पांडेय ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनीता का विशेष सहयोग रहा।

अपने ही चिराग से घर को आग न लग

जाए: दिनेश शर्मा

★ एनसीआर टुडे, अलीगढ़ ★

विजयश्री सिंह क्षत्रिय शिक्षा एवं विकास समिति, अलीगढ़ के तत्वावधान में स्वर्गीय विजयश्री सिंह की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सारस्वत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन तिब्बिया कॉलेज (एमएम), तस्वीर महल चौराहा स्थित ऑडिटोरियम हॉल में किया गया कार्यक्रम का अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष, हिंदी प्रचारिणी सभा, अलीगढ़ ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. देवेंद्र देव 'मिर्जापुरी' (बुलंदशहर) तथा सम्माननीय विभूति के रूप में प्रो. डॉ. मधु चतुर्वेदी (गजरोला) उपस्थित रहे।

आयोजक/संयोजक डॉ. ललित कुमार सिंह 'ललित' तथा सह-संयोजक अंबा सिंह 'अभय' झा (हाथरस) का संचालन प्रसिद्ध मंच संघालक डॉ. उपेन्द्र देहा (हाथरस) ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ राजेश चंद्र जैन (एटा) द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। तत्पश्चात अजय सिंह जादौन 'अर्पण' (खैर) ने ब्रज भाषा में बांके बिहारी को समर्पित छंद और खड़ी बोली में रचना प्रस्तुत की।

चच्चा उदयशानी ने ब्रज भाषा में भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित छंदों से समां बांधा प्रो. मधु चतुर्वेदी ने अपनी श्रृंगारी रचना से वातावरण को भावमय बना दिया। अभय सिंह 'अभय' ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचना प्रस्तुत की। बलवीर सिंह 'बैचैन' (तोछीगढ़, इगलास) ने ओजस्वी काव्य पाठ कर श्रोताओं का उत्साह बढ़ाया कृष्ण गुरती लाल 'मानव' (एटा) ने सामर्थिक रचना में समाज में घुरते भाईचारे पर चिंता व्यक्त की कवयित्री सीमा 'मंजरी' (मेरठ) ने शारदे वंदना, गीत-गजल और शबरी प्रसंग पर प्रभावी प्रस्तुति दी महेश 'मंजुल' ने मधुर मगही गीत गाया अरविंद भट्टी (बुलंदशहर) ने 'चलो गांव की ओर' गाया से श्रोताओं को भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित किया डॉ. उपेन्द्र झा (हाथरस) ने कृष्ण भक्ति पर छंद प्रस्तुत किए

दीपावली पर जगमगाती रोशनी से रोशन-

सफाई से गुलजार होगा शहर

हर पार्षद वार्ड में लगी नई 65 स्ट्रीट लाइट-5850 नई लाइट फोटो: 04-रत्न सेठ पर निरीक्षण करते नगर आयुक्त

★ एनसीआर टुडे, अलीगढ़ ★

दीपावली पर बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं को कराने के लिये नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अधीनस्थों के दायित्व निर्धारित करते हुए नगर निगम की एडवाइजरी जारी की है। नगर आयुक्त ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में दीपावली पर नगर निगम इंतजामों, पुलिस व जिला प्राइस के सहयोग और समन्वय को देखते हुए सभी थाना वाइज व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के 4 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक वरिष्ठ अधिकारी को सेक्टर प्रभारी नामित किया गया है।

इसके साथ साथ मुख्य अभियन्ता, महाप्रबंधक जल, मुख्य अभियन्ता यांत्रिक, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, पशु कल्याण अधिकारी, प्रभारी कंट्रोल रूम, प्रवर्तन प्रभारी, सभी क्लस्टर प्रभारियों जेनरल अधिकारियों के दायित्व निर्धारित करते हुये फ़िल्ड में मुरतैद रहने की सख्त हिदायत दी गयी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया दीपावली पर सभी धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाजारों, मुख्य-मुख्य मार्गों पर प्रकाश बिन्दुओं को प्रयोजित करने के लिये अधीनस्थों को सख्त हिदायत दी गयी है साथ ही सभी पार्षद वार्ड में पथ प्रकाश विभाग द्वारा 65 लाइट प्रति वार्ड में मुख्य मार्गों मोहल्लों में लगायी गयी है।

दीपावली पर नियमित पेयजल आपूर्ति व किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये जलकमल प्रांगण में पर्याप्त 30 पेयजल टैंकर भी रखवाये जायेंगे प्रमुख मार्गों पर टैंकर खड़े किये जायेंगे। उन्होंने बताया दीपावली 8 स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में अर्बन कम्पनी व 80 सफाई कर्मचारियों की नाइट स्वॉपिंग गैंग तैयार की गई है जिनके साथ 5 मैकेनिकल लोडर 80 टाटा टिपर 60 फॉर्गिंग 80 स्प्रे मशीन साथ रहेगी। नगर निगम का प्रयास दीपावली को देखते हुए रात में शहर के सभी प्रमुख स्थानों और मुख्य मुख्य बाजारों से कूड़ा उठाने का रेंगा इसलिए दुकानदारों से अपील की जाती है की दुकान बंद करने समय अपना दुकान और प्रतिष्ठान का कूड़ा रात में ही बाहर निकाले व रात में ही सफाई करें। उन्होंने बताया दीपावली को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कंट्रोल रूम को लगातार कार्यशील रखा गया है।

सीएम योगी बोले- अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हों तो किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करें

लखनऊ , एजेंसी।यूपी में अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना की राफ महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में रिफिल कराने का उपहार दिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन सभागार में उज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया। इस मौके पर उन्होंने रिफिल की धनराशि महिलाओं के खाते में भेजी। सीएम ने 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रिफिल की धनराशि मंच पर प्रदान की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी ने उज्वला योजना की लाभार्थी एक करोड़ 86 लाख महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी भेजी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले में खाना पकाना पड़ता था जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें जिंदगी भर इलाज करवाना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गये जिससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ।

रामभद्राचार्य बोले- ये बड़ी विडंबना है, राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लेने वालों को बना दिया ट्रस्टी



लखनऊ, एजेंसी। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि अजीब विडंबना है, जिन्होंने एक बार भी राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लिया, उन्हें ही मंदिर का ट्रस्टी बना दिया गया। वह मंगलवार को विजैथुआ महावीरन धाम में वाल्मीकि रामायण कथा सुना रहे थे।

रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि संतों ने गांव में जाना छोड़ दिया तो विसंगतियां बढ़ने लगीं। अवध और अवधी दोनों मुझे बहुत भाती हैं। यह मेरी और मेरे आराध्य की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को मस्तक पर



योगी सरकार ने आधी आबादी की सबसे ज्यादा चिंता की है

इस मौके पर यूपी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं वो आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी भी लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना से 26 लाख 24 हजार लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह सामूहिक विवाह योजना से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया गया है। वित्तमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए चल रही अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं की सबसे ज्यादा चिंता की है। उन्होंने कहा कि मुद्दे हरगिज न कर पाएगा बांका बाल तक, मोदी योगी गूजेगा भारत में जा सक्त तक।

नगर मे अजमीद जी महाराज की भव्य शोभायात्रा निकाली गई

★ एनसीआर टुडे, नहटौर ★

शैव क्षत्रिय सोनार सभा के तत्वावधान में मैट्ट महाराज अजमीद जी महाराज की शोभायात्रा भव्य रूप से अपने निर्धारित मार्गों से निकाली गई। शोभायात्रा में सबसे आगे घुड़सवार ध्वज लिए चल रहे थे। शोभायात्रा में भगवान गणेश जी, अजमीद जी महाराज, अचोरी अखाड़ा, राम दरबार आदि की झांकियाँ आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभायात्रा का कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

मौहल्ला चौधरियान स्थित आर्य समाज मंदिर से मैट्ट क्षत्रिय सोनार सभा के तत्वावधान में निकाली गई शोभायात्रा का शुभारंभ सेवानिवृत्त एसडीएम स्टेनो अशोक वर्मा, संरक्षक मारोहितास वर्मा, अध्यक्ष विपिन वर्मा, कोषाध्यक्ष विनिल वर्मा, नरेन्द्र वर्मा, मुकेश वर्मा, इंद्रदेव वर्मा आदि ने महाराजा अजमीद जी महाराज की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

शोभायात्रा में राधा कृष्ण, शिव पार्वती, कृष्ण सुदामा, अजमीद जी महाराज, अचोरी अखाड़ा, राम लक्ष्मण मीठा, हनुमान जी आदि की झांकियाँ शामिल रहीं।

तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाने के अनेक फायदे हैं। तिलक के बिना ब्राह्मण यमराज जैसा दिखता है।

तुलसी पीठाधीश्वर ने श्रद्धालुओं को बताया कि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पास गए। राजा से राम-लक्ष्मण को मांगा। इसपर दशरथ ने कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता।

वशिष्ठ के समझाने के बाद दशरथ ने राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। विश्वामित्र ने राम को विद्या प्रदान की। श्रीराम ने सबसे पहला ताड़का का किया।

गोहत्या कानून के दुरुपयोग पर यूपी पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- स्पष्ट फैसलों के बाद भी ये क्यों जारी

लखनऊ , एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले दर्ज करने के लापरवाही तारीक पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि स्पष्ट न्यायिक फैसलों के बावजूद ऐसे मामलों क्यों जारी हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है।

न्यायमूर्ति अन्दुल मौद्दनी और न्यायमूर्ति अब्दुल क़दिर चौधरी की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन न होने के बावजूद ऐसी एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही



हे? कोर्ट ने रहलु यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रहलु ने प्रतापगढ़ में गोहत्या अधिनियम की धारा 3, 5ए और 8 तथा पशु क़रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था।

रहलु यादव ने दलील दी कि उनका ड़ाहवर गाड़ी लेकर वापस नहीं लौटा और बाद में उन्हें पता

जाया जा रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि गोहत्या अधिनियम की धारा 5ए केवल अंतरराज्यीय परिवहन पर लागू होती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के वध या अपंगाता का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए धारा 3 और 8 लागू नहीं होंगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि, याचिकाकर्ता न तो वाहन का चालक था और न ही वाहन में मौजूद था, इसलिए पशु क़रूरता अधिनियम के प्रावधान प्रथम दृष्टया लागू नहीं होंगे। आदेश में खंडपीठ ने कोर्ट में आने वाली उच्च याचिकाओं की भारी संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिनमें व्यक्तियों को गोहत्या अधिनियम के तहत झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि इनमें किसी भी प्रकार का वध, चोट या अंतरराज्यीय परिवहन शामिल नहीं है।

पीठ ने कहा कि एफआईआर से यह पता चलता है कि पशु जीवित पाए गए थे और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्हें राज्य से बाहर ले

जाया जा रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि गोहत्या अधिनियम की धारा 5ए केवल अंतरराज्यीय परिवहन पर लागू होती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के वध या अपंगाता का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए धारा 3 और 8 लागू नहीं होंगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि, याचिकाकर्ता न तो वाहन का चालक था और न ही वाहन में मौजूद था, इसलिए पशु क़रूरता अधिनियम के प्रावधान प्रथम दृष्टया लागू नहीं होंगे। आदेश में खंडपीठ ने कोर्ट में आने वाली उच्च याचिकाओं की भारी संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिनमें व्यक्तियों को गोहत्या अधिनियम के तहत झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि इनमें किसी भी प्रकार का वध, चोट या अंतरराज्यीय परिवहन शामिल नहीं है।

बड़े भाई ने शराब के नशे में छोटे को पीटा

फिर कीचड़ में सिर दबाकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर , एजेंसी। कानपुर में बिदूर थाना क्षेत्र के पास प्रतापपुर गांव में मंगलवार आधी रात के बाद रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई। पीटा और अपने छोटे के भाई को बड़े भाई ने गला दबाने के बाद घर के ठीक सामने कच्ची सड़क के कीचड़ में सिर दबाकर मार डाला।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिदूर पुलिस ने आरोपी भाई को हिंस्रत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक के पिता रामशंकर ने बताया कि बड़ा बेटा कुंदन(35) मजदूरी करता है और शराब का लूती है। मंगलवार आधी रात को कुंदन शराब के नशे में आया और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सीता को डंडों से पीटा। जब रामशंकर ने विरोध किया, तो कुंदन ने उसे भी पीटा दिया। इसके बाद घर के पास

बने कमरे में सो रहे छोटे भाई विराट उर्फ चिरी (24) को चारपाई सहित पलट दिया और जमकर पीटा।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा : उसे पीटते हुए घर सामने कच्ची सड़क के कीचड़ में गला दबाकर मार डाला। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े। ग्रामीणों ने विराट को तब तक बिराट की सांसे थम चुकी थीं।

ग्रामीणों ने हत्यारोपी भाई कुंदन को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। रात करीब डेढ़ बजे बिदूर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आरोपी भाई को हिरासत में लेने के बाद मृतक के कुंदन सहित उसने अपनी पत्नी सीता को डंडों से पीटा। जब रामशंकर ने विरोध किया, तो कुंदन ने उसे भी पीटा दिया। इसके बाद घर के पास

सीएम योगी की अपील दिवाली पर स्वदेशी अपनाएं

सीएम योगी ने कहा कि दिवाली आ रही है। ऐसे में ध्यान रखें और स्वदेशी अपनाएं। दिया जलाएं तो अपने ही कुम्हार से बनाया हुआ हो। मूर्ति वहीं प्रयोग करें जो स्वदेशी मूर्तिकार की बनी हुई हो। दिवाली के मौके पर किसी गरीब की मदद जरूर करें।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में सैफई परिवार ही सबकुछ था। हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। सपा सरकार दगाहनों के सामने नाक रगड़ती थी और अपराधियों के साथ खड़ी होती थी पर हमने तय किया कि अब अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर यमराज से टिकट करवाना हो तो किसी बेटी से छेड़छाड़ कर दें। अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। हमने कहा है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। हर गरीब के साथ सरकार खड़ी होगी। हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी। उत्साह और उमंग में किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो उसे जेल में ठूसने में देर नहीं करेंगे। इसलिए आज हर त्योहार खुशी के साथ मनाया जा रहा है।

बता दें कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना की

शुरुआत मई, 2016 में हुई थी। इस योजना से खासकर ग्रामीण भारत की रसोई को धूप से मुक्त करने में सफलता मिली। साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई। प्रदेश में अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने उज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी रिफिल देने का निर्णय लिया है। यह वितरण विधायी वर्ष 2025-26 में दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन

★ एनसीआर टुडे, नहटौर ★

जिला बिजनौर में शासन द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद शिबारा मंत्राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सीमा के निदेशन में मिशन शक्ति रीट के तहत महिला सशक्तिकरण विषय पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं व अन्य छात्राओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव गौड़ द्वारा विस्तारपूर्वक समझाया गया। उनके द्वारा छात्राओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज भारत की बेटियों ने नए - नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनके प्रशिक्षण में उनका साथ दें। छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए शासन द्वारा जारी फोन नम्बरों का ज्ञान जरूर चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी करना



चाहिए। ये नम्बर है -181-(महिला हेल्पलाइन) राष्ट्रीय रत्न पर और 190(0) विमेन पावर लाइन) उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। आपतकालीन स्थितियों के लिए 112 डायल किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड के लिए 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नंबर है जिन्हें हमें अपने पास नोट करके रखना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम में कुछ छात्राओं ने महिलाओं से जुड़े सपन भी पूछे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव गौड़ जी ने छात्राओं को शुभकामनाएं व बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने छात्राओं का उत्साह वर्धन किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का योगदान सराहनीय योगदान रहा।

दीक्षांत समारोह ज्ञान और प्रेरणा का उत्सव है : राज्यपाल

★ एनसीआर टुडे, अलीगढ़ ★

राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त समारोह बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित शैला गौतम सेंटर फॉर लॉजिंग सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुआ। दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि प्रो0 कमल कुशौर पंत निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की, विशिष्ट अतिथि योगेन्द्र उपाध्याय मंत्री (उच्च शिक्षा) एवं रजनी तिवाड़ी, माननीय राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा) कर गरिमामयी उपस्थिति रही।

वीए की छात्रा को वेतनर ऑफ आर्ट के स्वर्ण पदक व मिली उपाधि



विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर गोद लिए ग्रामों के विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिताओं में क्रमशः पल्लवी उपाध्याय, मीना कुमारी एवं मुस्कान को उपहार एवं प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अलीगढ़ एवं हाथरस के आंगनबाड़ी केंद्रों

को सशक्त बनाने के लिए 500 किटों का वितरण किया गया। जिनमें अलीगढ़ की पत्नी साहिबाबाद की आंगनबाड़ी नविता निर्मल, सराय कला की गुजल, अटलपुर की कु0 भावना, लोधा की संगम, नादा बाजिदपुर की राधा तोमर एवं हाथरस की अंजना, रूक्मती, सुमन, कांता व प्रीती को प्रतीक स्वरूप मंच पर किट प्रदान की गई।

कुलाधिपति ने राजभवन द्वारा संकलित 05-05 पुरस्कों को जिलाधिकारी अलीगढ़ संजीव रंजन एवं सीडीओ हाथरस पी0एन0 दीक्षित को भेंट करने के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी पुरस्कों प्रदान कीं। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में बनिने वाली रूषणिक भवन-3 एवं अतिथिद्वारा हब की डिजिटली शैक्षणिक रीमोट का बटन दबाकर शिलान्यास किया।

काम हम सही ढंग से करेंगे वही प्रथा बन जाएगी राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि जो काम हम सही ढंग से करेंगे वही प्रथा बन जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन-अध्यापन के साथ ही अनुशासन आवश्यक है। हमें दूसरे विश्वविद्यालयों से भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी है। जिन छात्रों में प्रतिभा है उनको आगे बढ़ाने का

कार्य करें। उन्होंने बताया कि आज 51 हजार से अधिक उपाधियों को डिजिटलकर में संरक्षित किया गया है, जिससे प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी, फर्जी डिग्रियों का खेल खत्म होगा।

छात्र कभी भी अपने दस्तावेजों को डिजिटलकर से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं, हमने नवीन तकनीक के माध्यम से समाधान निकाला। हमारे पास विभिन्न विश्वविद्यालयों में 15 लाख से अधिक उपाधियां थीं जिनका वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य संवारने के लिए आपको पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। विद्यार्थी हित में हमने कठोर निर्णय लेते हुए परिश्रम में बेठठान के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वागत किया कि जब पढ़ेंगे नहीं तो साक्षात्कार में पंचा बताएंगे। कुलाधिपति ने छात्रों को सचेत किया कि टैलेटों को आगे बढ़ाएं, शॉर्टकट न ढूढ़ें, गुरुजनों के अनुभव का लाभ लेते हुए गुरु-शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं।

गणेश कैसर से बवाने के लिये दो डोज एचपी वैक्सीन-आन्दीबेन पटेल कुलाधिपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एचपीवी वैक्सीन

अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि 09 से 15 की बालिकाओं को डिजिटलकर में संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि सही समय पर परीक्षाएं आयोजित कराएं ताकि विद्यार्थियों को समय से परिणाम निर्गत किए जा सकें।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा विकसित समर्थ पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। पोर्टल में 42 मॉड्यूल शामिल हैं जिनमें एडमिशन से लेकर परीक्षा परिणाम तक की सुविधा है। उन्होंने बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता के साथ से अकेले उत्तर प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 01 लाख पैथोरोपण के लक्ष्य को पूर्वनियोजित कार्यक्रमों के अनुसार पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भवन निर्माण के समय ही फर्नीचर का भी बजट सुनिश्चित करने के साथ ही निरीक्षण टीमों द्वारा सुधार और



निगरानी प्रक्रिया जारी रखने की बात कही। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में स्वच्छता, नशामुक्त जीवन और बेटियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर को नशामुक्त बनाए रखने का संकल्प लेने की भी बात कही। अपने उद्घोष के अंत में उन्होंने कहा कि आज मिलने वाला यह पदक धातु का नहीं बल्कि उज्वल भविष्य का मार्गदर्शन है। संवाद सकारात्मक सोच रखें और अपने प्रयासों से समाज और राष्ट्र की प्रति में योगदान दें।

दीक्षान्त समारोह में सांसद हाथरस अनूप बाल्मीकि, अध्यक्ष जिला पंचायत विजय सिंह, विधायक इगलास रामकुमार सहयोगी, मण्डलायुक्त संगीता सिंह, डीआईजी प्रभाकर चौधरी, जिलाधिकारी संजीव रंजन, एसएसपी नीरज कुमार जादौन, सीडीओ प्रवीर कुमार सिंह, अपर आयुक्त एवं कुलसचिव वी. के. सिंह समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं विश्वविद्यालय के अध्यापकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



87 रन बनाना काफी नहीं!

पूर्व चयनकर्ता ने साई सुदर्शन को दिया गंभीर संदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के पूर्व चयनकर्ता अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तमिलनाडु के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को आगामी सीरीज में टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर चुनने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्रीकांत के अनुसार, सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में समाप्त हुई श्रृंखला के दौरान मिले अवसरों को पूरी तरह भुनाया नहीं।

यशस्वी जायसवाल की तारीफ

श्रीकांत ने यशस्वी जायसवाल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने मुंबई के इस बल्लेबाज को तीनों प्रारूपों में खेलने वाला खिलाड़ी बताया। श्रीकांत ने कहा, +टी20 में उनका रिकॉर्ड शानदार है, वनडे में भी वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनका खेल स्वाभाविक है और वह बिना किसी बदलाव के अपना खेल खेलते हैं। मध्यम गति के गेंदबाजों पर भी वह आक्रमण करते हैं और कई बार उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन उन्हें अब तक वनडे और टी20 में पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। उनकी औसत 36+ और स्ट्राइक रेट 164+ ने उनकी क्षमताओं को उजागर किया है।

मिला-जुला प्रदर्शन, शतक से चूक

दिल्ली टेस्ट में सुदर्शन ने तीन पारियों में क्रमशः 3, 87 और 39 रन बनाए। सात पारियों में केवल एक अर्धशतक के साथ उन्होंने शुरुआत में प्रभाव दिखाया, लेकिन शतक न बना पाने से उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। श्रीकांत ने कहा, 87, 99 और 100 के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बार जब आप शतक बना लेते हैं, तो यह एक अलग ही स्तर होता है। यही सुदर्शन के लिए फिलहाल कमी साबित हुई।

आर्चरी प्रीमियर लीग

भारतीय तीरंदाजी में एक नया अध्याय

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन भारतीय तीरंदाजी संघ ने किया, जिसमें दुनियाभर के कई सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों ने अपनी चमक बिखेरी। इस लीग में छह टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें कुल 48 तीरंदाज शामिल थे। इनमें 36 भारतीय और 12 विदेशी थे। आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एक साथ खेले, जिसमें युवा तीरंदाजों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला। इनमें कुछ विदेशी दिग्गज भी शामिल थे, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय मुकाबलों का अनुभव मिला। इसने यकीनन उनके प्रदर्शन और मानसिक मजबूती को बेहतर बनाने में मदद की। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का पहला राउंड-रॉबिन चरण 2-6 अक्टूबर और दूसरा 7-11 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। इस दौरान प्रत्येक प्लेइंग लाइनअप में कम से कम एक विदेशी तीरंदाज को शामिल किया गया था, जिन्होंने मिश्रित रिकॉर्ड और कंफाउंड तीरंदाजी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में दो राउंड-रॉबिन चरण हुए, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबलों का आयोजन किया गया, जिनमें सेमीफाइनल और फाइनल शामिल थे। राउंड-रॉबिन चरण में रोजाना तीन



मुकाबलों का आयोजन हुआ। फ्लडलाइट में खेले गई प्रत्येक प्रतियोगिता 20 मिनट की हुई। इसमें प्रत्येक तीरंदाजी के लिए 15 सेकंड का समय दिया गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यह समय 20 सेकंड होता है।

इस लीग में एरो शूटिंग की दूरी ओलंपिक मानक के अनुरूप ही थी। रिकॉर्ड के लिए 70 मीटर, जबकि कंफाउंड के लिए 50 मीटर के लिए दूरी तय की गई। आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) में इन छह टीमों ने राउंड-रॉबिन चरण में एक-दूसरे का सामना किया। दोनों राउंड-रॉबिन चरणों के बाद शीर्ष चार टीमों नॉकआउट चरण में पहुंचीं,

जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले गए। राजस्थान की टीम राजपूताना रॉयल्स ने दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा को हराकर गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम की। तीरंदाजी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। मध्य पाषाण युग के उत्तरार्ध से धनुष-बाण का प्रयोग होता था, लेकिन ओलंपिक ने इसे आधुनिक खेल के रूप में लोकप्रिय बनाया। 1900, 1904, 1908 और 1920 के ओलंपिक में तीरंदाजी को शामिल किया गया। ओलंपिक 1904 में यह महिलाओं की स्पर्धाओं को शामिल करने वाले पहले खेलों में से एक था। लेकिन तीरंदाजी के प्रारूप असंगत थे।

द. अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, कतर और सऊदी अरब ने ववलिफाई किया

यूरोप से इंग्लैंड बनी पहली टीम

लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड ने लाटविया पर 5-0 की बड़ी जीत के साथ विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया और इस तरह यूरोप का पहला देश बना जिसने टूर्नामेंट में जगह पक्की की। अफ्रीका से विश्व कप 2026 के लिए तीन बड़ी टीमों- दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट और सेनेगल ने अपना टिकट पक्का कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को रवांडा को 3-0 से हराकर अपने क्वालिफाईंग ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह 2010 के बाद पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका फीफा विश्व कप में हिस्सा लेगा। इस जीत के साथ ही नाइजीरिया को अपने ग्रुप में दूसरा स्थान मिला और उसे अब प्लेऑफ के जरिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि नाइजीरिया ने बेनिन को उसके घरेलू मैदान पर विक्टर ओसिमैन की हैट्रिक की बदौलत 4-0 से हराया। उधर, आइवरी



कोस्ट ने कीनिया पर 3-0 की जीत दर्ज कर सीधा क्वालिफिकेशन हासिल किया, जबकि सेनेगल ने मॉरिटानिया को 4-0 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप में जगह बनाई।

एशिया से कतर और सऊदी अरब का टिकट पक्का- एशियाई क्वालिफायर के चौथे दौर में कतर और सऊदी अरब ने अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर विश्व कप 2026 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। कतर ने दोहा में खेले गए ग्रुप में संयुक्त अरब अमीरात को 2-1 से हराया, जबकि सऊदी अरब ने जेद्दा में इराक के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला। दोनों टीमों अब एशिया से विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सातवीं और आठवीं टीम बन गई हैं। कतर दूसरी बार विश्व कप में हिस्सा लेगा। पिछली बार वह मेजबान देश के रूप में खेला था। लेकिन इस बार कतर ने अपने दम पर क्वालिफिकेशन हासिल किया, जो उसके फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय है। सऊदी अरब अब तक सातवीं बार विश्व कप में हिस्सा लेने जा रहा है। इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, उज्बेकिस्तान और जॉर्डन एशिया से जून में ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

एफसी एशियन कप 2027 से भारत हुआ बाहर

सिंगापुर ने 2-1 से हराया

गोवा, एजेंसी। भारतीय फुटबॉल टीम का सत्र एशियन कप 2027 में क्वालिफाई करने का सपना सिंगापुर के हाथों टूट गया। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के रोमांचक मुकाबले में भारत को 2-1 से हार झेलनी पड़ी। मैच की शुरुआत भारत ने जोश के साथ की और 14वें मिनट में लालियानजुआला छांगते ने लगभग 30 गज की दूरी से शानदार गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह गोल देखने लायक था और दर्शकों में जोश भर गया। हालांकि, इसके बाद भारत कई मौकों



को भुना नहीं सका। सुनील छेत्री, महेश नाओरेम और लिस्टन कोलाको ने अच्छे मौके गंवाए, जिससे टीम बढ़त नहीं बढ़ा सकी। पहले हाफ के आखिरी मिनटों में भारत को रक्षात्मक चूक का फायदा सिंगापुर ने उठाया। राहुल भेके की गलती से मिले मौके पर ग्लेन क्रैह ने बॉल सॉन्ग यूई-यंग को पास की, जिन्होंने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निखिल प्रभु की चूक से सिंगापुर को एक और मौका मिला, जिसे यूई-यंग ने गोल में तब्दील करते हुए टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई। भारत ने इसके बाद बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया। साहल अब्दुल समद, ब्रैडन फर्नांडिस, फरुख चौधरी और उदंता सिंह को उतारकर कोच खालिद जमील ने आक्रमण तेज किया, लेकिन सिंगापुर की रक्षापंक्ति ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत अब ग्रुप सी में चार मैचों में सिर्फ दो अंकों के साथ सबसे नीचे है। टीम ने बांग्लादेश (0-0) और सिंगापुर (1-1) से ड्रॉ खेले, जबकि हांगकांग चीन (0-1) और अब सिंगापुर से हार गई। इस हार के साथ भारत का एफसी एशियन कप 2027 का सफर यहीं समाप्त हो गया।

मोहम्मद सिराज को मिला मेहनत का फल

खास ऑर्ड के साथ रवाना हुए ऑस्ट्रेलिया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर मेडल से सम्मानित किया गया है। सिराज ने इस सीरीज में कुल 10 विकेट हासिल किए, जो सभी तेज गेंदबाजों में सबसे अधिक थे। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से जीती गई टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित



किया। अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने हरी पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए 7 विकेट झटकें, जिसकी मदद से भारत ने पारी और 140 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि, दिल्ली में हुए दूसरे टेस्ट में पिच तेज गेंदबाजों के लिए कम मददगार थी, लेकिन सिराज ने कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्होंने पूरी सीरीज में 49 ओवर गेंदबाजी की जो कि जसप्रीत बुमराह के 5 1.5 ओवरों से थोड़ा ही कम था। ड्रेसिंग रूम में उन्हें यह इम्पैक्ट प्लेयर मेडल विकेटकीपर-बल्लेबाज एन जगदीशन ने दिया। इस सम्मान पर सिराज ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो यह सीरीज बहुत अच्छी रही... यहां दिल्ली में एक विकेट लेना भी पिच विकेट लेना जैसा महसूस हो रहा था। क्योंकि एक तेज गेंदबाज के तौर पर जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुश भी होते हैं।

महिला वर्ल्ड कप

भारत को लगा दोहरा झटका

ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद 'जेब भी कटी'



हरमनप्रीत कौर ने गलती मानी

नई दिल्ली, एजेंसी। महिला वर्ल्ड कप में रविवार (12 अक्टूबर) को विशाखापत्तनम में भारतीय टीम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस के पांच प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 330 रनों का लक्ष्य एक ओवर और तीन विकेट शेष रहते हासिल कर लिया था। भारतीय निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाया गया। यह जुर्माना आईसीसी इंटरनेशनल पैरल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने लगाया। प्लेयर एंड प्लेयर स्पॉट स्टाफ के लिए न्यूनतम ओवर रेट से संबंधित आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की आर्टिकल 2.22 के तहत खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

इब्राहिम जदरान कोहली और रोहित से आगे निकले

जायसवाल और कुलदीप को आईसीसी रैंकिंग में बढ़त



नई दिल्ली, एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा रैंकिंग अपडेट में भारतीय और अफगान खिलाड़ियों ने शानदार छलांग लगाई है। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने वनडे बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछड़ दिया है, जबकि भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही कुलदीप यादव और राशिद खान जैसे स्पिनरों ने भी अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है।

जायसवाल ने साबित किया क्लास, बने भारत के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज-वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में नई पहचान बनते जा रहे हैं। दिल्ली टेस्ट में पहली पारी में खेले गए 175 रनों की शानदार पारी ने उन्हें टेस्ट रैंकिंग में दो स्थान ऊपर पहुंचाया है। अब जायसवाल पांचवें स्थान पर हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। युवा बल्लेबाज का यह लगातार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत को भविष्य के लिए एक लंबी रेस का धाक मिल चुका है।

इब्राहिम जदरान की ऐतिहासिक छलांग, कोहली-रोहित से आगे निकले

अफगानिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार 213 रनों की पारी खेलकर वनडे रैंकिंग में नया इतिहास रचा। उन्होंने आठ स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। इब्राहिम के अब 764 रैंकिंग अंक हैं, जो विराट कोहली (736) और रोहित शर्मा (756) दोनों से ज्यादा हैं। यह पहली बार है जब किसी अफगान बल्लेबाज ने वनडे रैंकिंग में इतना ऊँचा स्थान हासिल किया है। राशिद खान बने नंबर-1 गेंदबाज, उमरजई ने भी मारी बाजी-स्पिन के जादूगर राशिद खान ने एक बार फिर साबित किया कि वह सीमित ओवरों के बेताज बादशाह हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टीम मैचों में 11 विकेट लेकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पछाड़ते हुए वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई ने भी रैंकिंग में इतिहास रच दिया है।

भारतीय खिलाड़ी डरते हैं... अजिंक्य रहाणे ने बीसीसीआई सेलेक्टर्स पर साधा निशाना!



नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम सेलेक्शन पर बड़ा बयान दिया है। रहाणे ने कहा कि भारत में खिलाड़ियों के सेलेक्शन प्रोसेस में बड़े बदलाव की जरूरत है। रहाणे ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी सेलेक्टर्स के डर से खुलकर नहीं खेल पाते और इससे टैलेंट दब जाता है। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भारतीय क्रिकेट में सेलेक्शन सिस्टम को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। रहाणे का मानना है कि सेलेक्टर्स की नियुक्ति में बुनियादी सुधारों की जरूरत है। खासकर ड्रेमेस्ट लेवल पर... उन्होंने कहा कि टीम चुनने की जिम्मेदारी केवल हाल ही में रिटायर हुए फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे मॉडर्न क्रिकेट की डॉट्स और खिलाड़ियों की क्षमता को बेहतर समझते हैं। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इस साल की शुरुआत में मुंबई टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया था। रहाणे के इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि कई खिलाड़ी वर्तमान सेलेक्टर्स के डर से खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते, और इसलिए सिस्टम में बदलाव बेहद जरूरी है।